डा॰ मुरली मनोहर जोशी: ज्वाइंट रेस्पॉसिबिलिटी होने पर...(व्यवधान)...सरकार की तरफ से जवाब देना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sometimes, the information is not available *(Interruptions)*...Your can find out. *(Interuptions)* ...(व्यवधान)...जो भी पूछ कर जवाब दे देंगे।... *(Interruptions)*....

श्री वीरभद्र सिंह: सर, मुझे सवाल पूछने का मौका दीजिए।

श्री उपसभापति: मैं आपको मौका दे रहा हूं।...(व्यवधान)...आप पूछिए।

श्री वीरभद्र सिंह: सर, मंत्री जी बैम्बू के बारे में जो बता रहे हैं, यह फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उड़ीसा की पॉपुलरटी ऐसी है कि बैम्बू फारेस्ट में भी और देहात में भी है। यह एग्रिकलचर सब्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्रश्न यह आता है कि मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में, नार्थ ईस्ट में बैम्बू की जो कारीगरी होती है, यह बिल्कुल स्माल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ा है। इसीलिए नार्थ-ईस्ट में जो सुन्दर-सुन्दर बैम्बू के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। इसलिए उड़ीसा में होगा तो कब होगा, इस पर मंत्री साहब जवाब दें।

श्री उपसभापति: उनको यह पूछना है कि बैम्बू को स्माल स्केल इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं तो आपकी मिनिस्ट्री में इसका क्या प्रोग्राम है? ...(व्यवधान)...

श्री महावीर प्रसाद : श्रीमान् मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि हो सकता है उनके पास बांस न हो। मेरे पास खुद बांस है और मैं खेतिहर किसान हूं, इसलिए इसकी महत्ता को देखते हुए, मैं कृषि मंत्रालय से बात करके, इनको बता दूंगा कि क्या क्या मूल्यांकन है और हम क्या कर सकते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अच्छा रिप्लाई दिया है और उसकी इम्पोर्टेंस को वे जान गए हैं और वे कोशिश करेंगे । क्वेश्चन 205

देश में लौह-अयस्क के भंडार

*205. श्री अजय मारू: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में लौह-अयस्क के भंडार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) लौह अयस्क के भंडारों का पता लगाने के लिए झारखंड तथा अन्य राज्यों में अंतिम सर्वेक्षण कब कराया गया था; और

(ग) खनिज भंडारों की खोज हेतु सर्वेक्षण कितने अंतराल में कराया जाता है?

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख गया है।

विवरण

देश में लौह अयस्क के भंडार

(क) देश में 1.4.2005 तक लौह अयस्क के संसाधनों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:

(मिलियन टन में)

राज्य	कुल लौह अयस्क संसाधन (पी)
आंध्र प्रदेश	1598.108
असम	27.980
बिहार	0.644
गोवा	803.169
झारखंड	3984.431
कर्नाटक	8897.066
छत्तीसगढ़	2650.833
मध्य प्रदेश	200.006
महाराष्ट्र	277.420
उड़ीसा	4013.636
राजस्थान	541.982
तमिलनाडु	481.876
उत्तर प्रदेश	38.000
केरल	83.435
नागालैंड	5.280
कुल	23603.866

नोट: (पी) = अनंतिम स्रोत (आई॰बी॰एम॰, नागपुर)

(ख) जी एस आई द्वारा अलग-अलग राज्यों में किया गया लौह अयस्क भंडारों का अंतिम सर्वेक्षण निम्नवत है:—

झारखंड - 1980-81 - वर्ष 2005-06 में सर्वे दुबारा शुरू किया गया है।
कर्नाटक - 1981-82 - वर्ष 2005-06 में सर्वे दुबारा शुरू किया गया है।
उड़ीसा - 1981-82 - वर्ष 1997-98 में दुबारा शुरू किया गया जो अभी तक चल रहा है।
गोवा - 1983-84 - दक्षिण गोवा में 1997-98 दुबारा शुरू किया गया और यह 2000-01 तक चलता रहा।
मध्य प्रदेश- 1997-98 - और 1998-99 तक चलता रहा।

(ग) खनिज भंडारों की खोज के लिए सर्वेक्षण का कोई निश्चित अंतराल नहीं है।

Iron-ore reserves in the country

†*205. SHRI AJAY MAROO: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) the details of the iron-ore reserves in the country at present, State-wise;

(b) the date on which the last survey was conducted to ascertain the reserves of iron-ore in Jharkhand and other States; and

(c) the interval of time at which survey for exploration of mineral reserves is carried out?

THE MINISTER OF MINES (SHRI SIS RAM OLA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The details of resources of Iron Ore upto 1.4.2005 in the country as per UNFC are given below:

(in million tonnes)

STATE	TOTAL IRON ORE RESOURCES (P)
Andhra Pradesh	1598.108
Assam	27.980
Bihar	0.644
Goa	803.169
Jharkhand	3984.431
Karnataka	8897.066
Chhattisgarh	2650.833
Madhya Pradesh	200.006
Maharashtra	277.420
Orissa	4013.636
Rajasthan	541.982
Tamil Nadu	481.876
Uttar Pradesh	38.435
Kerala	83.435
Nagaland	5.280
	23603.866

†Original notice of the question was received in Hindi.

NOTE: (P) = PROVISIONAL Source(IBM, Nagpur)

(b) The last survey of Iron-ore reserves was conducted by GSI in different states as under:

Jharkhand	- 1980-1981.	Reinitiated in the year 2005-06.
Karnataka	- 1981-1982.	Reinitiated in the year 2005-06.
Orissa	- 1981-1982.	Reinitiated in the year 1997-98 and continuing since then.
Goa	- 1983-1984.	Reinitiated in South Goa in 1997-98 and continued till 2001-01.
Madhya Pradesh	- 1997-1998.	And continued till 1998-99.

(c) There is no fixed time interval for conducting exploration of mineral reserves.

श्री अजय मारू: उपसभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने एक अप्रैल, 2005 को देश के विभिन्न राज्यों में लौह अयस्क के जो भंडार हैं, उनकी provisional, अंतरिम सूची दी है। उसी के पार्ट ''ख'' में उन्होंने कहा है कि भारत में लौह अयस्क के जो भंडार हैं, उनके दो-तिहार्द भंडार झारखंड, कर्नाटक और उड़ीसा में हैं। इन राज्यों में जो सर्वेक्षण हुआ है, वह आज से 25 वर्ष पूर्व हुआ है और वर्ष 1980-81 में इन तीनों राज्यों में सर्वेक्षण हुए हैं, इसके बाद अभी झारखंड में वर्ष 2005-06 में, कर्नाटक में वर्ष 2005-06 में और उड़ीसा में 1997-98 में पुन: सर्वेक्षण आरंभ किया गया है। अपने उत्तर के ''ग'' भाग में मंत्री जी ने कहा है कि खनिज भंडारों की खोज के लिए सर्वेक्षण का कोई निश्चित अंतराल नहीं होता। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि निश्चित अंतराल तो नहीं होता, लेकिन वर्ष 1980-81 में सर्वेक्षण हुआ, उसके बाद 25 वर्षों बाद सर्वेक्षण करने का क्या कारण है, जब कि पिछले सत्र के अंतिम दिन यानी 23.12.2005 को मंत्री महोदय ने कहा था कि सर्वेक्षण हमेशा चलता रहता है और अभी भी चल रहा है। मंत्री जी के दोनों बयानों में अंतर है, मैं चाहता हूं कि वे इसे स्पस्ट करें।

श्री शीश राम ओला: उपसभापति जी, राज्य सरकारें जब मांग करती हैं कि हमारे राज्य में iron-ore का सर्वेक्षण शुरू किया जाए, उनकी मांग आने के बाद निर्णय होता है कि कौन-कौन से राज्यों में सर्वेक्षण शुरू किया जाए। झारखंड के लिए वर्ष 1980-81 में सर्वेक्षण हुआ, दोबारा वर्ष 2005-06 में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, कर्नाटक में वर्ष 1980-81 में सर्वेक्षण शुरू हुआ, दोबारा वर्ष 2005-06 में हुआ और अब भी चल रहा है, यही स्थिति उड़ीसा की भी है। जहां-जहां भी प्रदेश सरकारें सर्वेक्षण चाहती हैं, सहयोग देती हैं, वहां जितनी देर से वे सर्वेक्षण चाहते हैं, सर्वेक्षण चलता रहता है ...(व्यवधान)

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, again the source is IBM, Nagpur. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; no, second supplementary.

SHRI DINESH TRIVEDI: It is IBM, Nagpur. Sir, what is happening here? ...(*Interruptions*)... What is this? ...(*Interruptions*)... The source is IBM, Nagpur. How can you have this in Parliament? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What is this?

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, it is IBM, Nagpur. Sir, IBM, Nagpur is the source. Where are we going in this Parliament? Is this Parliament getting privatised? ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Maroo, second supplementary.

श्री अजय मारू: उपसभापति जी, स्टील मिनिस्टर, श्री राम विलास पासवान जी ने यह घोषणा की है कि वर्ष 2020 तक हमारे देश का स्टील का प्रोडक्शन 130 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा और उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो भंडार है, वह अगले एक वर्ष तक स्टील के प्रोडक्शन के लिए पर्याप्त है। महोदया, हमारे देश से काफी बड़ी मात्रा में iron-ore का एक्सपोर्ट हो रहा है और उस एक्सपोर्ट के बदले हम hard coke इंपोर्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो देश हमसे iron-ore इंपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास इसके पर्याप्त भंडार हैं, चाहे वह आस्ट्रेलिया हो, चाहे चीन हो, उनके पास iron-ore के पर्याप्त भंडार हैं, लेकिन वे अपने भंडार का खनन नहीं करते हैं और भारत से iron-ore मंगाते हैं। दूसरी तरफ कोयले के साथ-साथ लौह अयस्क का भी अवैध खनन हो रहा है, केवल झारखंड ही नहीं, सभी जगह इसका अवैध खनन हो रहा है और अवैध खनन के माध्यम से, इस iron-ore को एक्सपोर्ट किया जाता है। मैं सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब हमें वर्ष 2020 तक 130 मिलियन मीट्रिक टन स्टील का निर्माण करना है, एक अनुमान के हिसाब से इसके लिए हमें प्रति वर्ष ढाई सौ मिलियन मीट्रिक टन iron-ore की आवश्यकता होगी, तो क्या iron-ore के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की सरकार की कोई मंशा है?

श्री शीश राम ओला: उपसभापति जी, जीएसआई के सर्वेक्षण के अनुसार ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: यह इम्पार्टेंट क्वैश्चन है, आप जवाब सुनिए।

श्री शीश राम ओला: जीएसआई के सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में करीब 23,603 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर का भण्डार भारत में उपलब्ध है। आयरन ओर का उत्पादन प्रतिवर्ष 142 मिलियन मीट्रिक टन है और देश में आयरन की कुल खपत 45.49 मिलियन मीट्रिक टन है। इसके अलावा 10 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर इस्पात बनाने के काम आता है। इस प्रकार 96 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर सरप्लस है। यदि उसे कहीं नहीं भेजा गया, नहीं बेचा गया, तो जो मजदूर आयरन ओर निकालते हैं, खानों में काम करते हैं, वे सब बेरोजगार हो जाएंगे और उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यहीं नहीं ...(व्यवधान)... मुझे उत्तर देने दीजिए, घबराइए मत। देश में वर्ष 2020 में करीब 176 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर की जरूरत

पड़ेगी। इस हिसाब से हमारे पास 23,603 मिलियन मीट्रिक टन आयरन ओर के संसाधन हैं, वे पर्याप्त हैं। संसाधन व उत्पादन में हर लिहाज से भारत बहुत अच्छी स्थिति में है।

श्री अजय मारू: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मैंने यह पूछा कि दूसरे देश ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: आपका क्वैश्चन यही है न कि आप यह जानना चाहते हैं कि दूसरे मुल्क में रॉ मैटेरियल के ज्यादा रिसोर्सेज रहने के बावजूद भी वे हमारे मुल्क से इसका एम्पोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या पॉलिसी है? आप यही पूछना चाहते हैं न?

श्री शीश राम ओला: महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि 'क', 'ख' और 'ग' में जो प्रश्न पूछा गया है, तो 'क' और 'ख' की सही जानकारी मैंने हाउस में प्रस्तुत कर दी है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister was talking about exploration ...(*Interruptions*)...

श्री जयन्ती लाल बरोट: सर, इन्होंने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब तो मंत्री जी ने दिया नहीं, ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: मैं उन्हें यह नहीं कह सकता कि वे स्पेसिफिक जवाब दें ...(व्यवधान)... उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका एक्सेस भण्डार है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir the hon. Minister has explained that India has got excess of iron ore and, therefore, we are exporting it. My question to the hon. Minister is not only on survey, but also on expansion. I would like to ask him about value addition. Iron-ores have been taken from Orissa, Jharkhand, Madhya Pradesh and other places and industries have been set up there. So many companies have come up and set up industries there. They have been saying that they would set up the industries and get value addition. But, unfortunately, it is not being done. They are only exporting iron-ore, violating the terms and conditions. The hon. Minister was talking about employment potential; he was saying that value addition would increase the employment potential. Why is it not being done? That is one question.

The issue of tribals is daunting in that area. The tribal people who have lost their lands have demanded employment and increase in the amount of compensation for their lands, as also rehabilitation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That does not form part of the question.

SHRI V. NARAYANASAMY: Is the Government evolving a policy to protect the interests of the tribals who have lost their lands because they gave it to the companies for the purpose of exploring iron-ore?

These are the two questions that I would like to ask the hon. Minister

श्री शीश राम ओला: उपसभापति जी, एक हुड्डा कमेटी का गठन किया गया है जिस की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। इस में जो विसंगतियां हैं, वे इस रिपोर्ट के आने के बाद माननीय सदस्यों की सलाह से हम उस रिपोर्ट के मुताबिक दूर करने की चेष्टा करेंगे।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, for both questions, no reply has come. ...(*Interruptions*)... The Minister of State is also here. He can also reply ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Narayanasamy, please sit down. ...(*Interruptions*)... Hon. Member is putting his question. ...(*Interruptions*)...

श्री शरद अनंत राव जोशी।

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: The difference between documents given by the documentation Centre and the replies given by the Minister is disappearing fast. I did not understand IBM. Normally, IBM means International Business Machines. If you want to use it ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No. it is Indian Bureau of Mines. ...(*Interruptions*)...

SHRI SHARAD ANANTRAO JOSHI: I know that this means Indian Bureau of Mines, but this should have been clarified. Similarly, what is UNFC? I don't know ...(*Interruptions*)...

श्री नीलोत्पल बसु: सर, इस सदन में एक आम सहमति है कि यहां से आयरन ओर का निर्यात हो रहा है। यह जो उत्तर दिया गया है, मेरे ख्याल में इस में भी ''हेमाटाइट'' और ''मैग्नेटाइट'' अलग से देने से फायदा होता क्योंकि हमारे स्टील प्रोडक्शन में हम मैग्नेटाइट काम में नहीं ला सकते। सर, मेरा सवाल यह है कि सरकार की जो खनिज नीति है, इस में अगर किसी प्रदेश में स्टील प्रोडक्शन के लिए कोई यूनिट लगाना चाहता है, उस को उन प्रदेशों में जहां पर खनिज आयरन ओर उपलब्ध है, डिनाई किया जाता है। दूसरी तरफ इसे खुले आम विदेश में निर्यात करने की इजाजत है। साथ ही सरकार की ओर से मंत्री जी जो आंकड़े दे रहे हैं, यह भी विवादास्पद है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है, उस हिसाब से यह आयरन ओर हेमाटाइट कितने दिन चलेगा? तो ये दो चीजें मंत्री जी स्पष्ट कर दें। सही में हमारा हेमाटाइट का जो डिपॉजिट है, वह हमारे वर्तमान ग्रोथ रेट में स्टील की जो खपत है, उस हिसाब से कितने दिन चलेगा? दूसरी बात यह कि क्या साथ-साथ आयात की नीति भी चलेगी और दूसरी ओर जिन प्रदेशों में स्टील प्रोडक्शन के लिए लिंकेज मांगा जाता है, उस की भी उपेक्षा की जाएगी?

श्री शीश राम ओला: सर, माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात पूछी है। सर, राज्य सरकारों को पूरा अधिकार है कि वे लोहा दें। हमारे पास, भारत सरकार के पास तो यह केवल प्रि-अप्रूवल के

लिए आता है और वह हम देते हैं। सर, माननीय मुख्य मंत्री, बंगाल ने भी प्राइम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी थी, उस का उत्तर भी मैंने दे दिया है। सर, ये सारे मसले ''हुड्ड'' कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हल होंगे और इस में जो विरोधाभास है, उस का अंतर कम हो, यह हम कोशिश कर रहे हैं।

DR. K. MALAISAMY: Sir, when we went, as a Committee, to ISRO, we were told by ISRO that they have got a system of remote sensing to find out what are the various resources available in our country. They have got a detailed survey State-wise. From the answer I am able to see tools or the agency you have employed are UNFC or GSI. I would like to know specifically whether you have got an overall survey of remote sensing. If so, is it intensive or superficial? why do you depend upon only these two resources? Why not remote sensing also.

श्री उपसभापति: वे जो जानना चाहते हैं, बताइए।

श्री शीश राम ओला: वे क्या जानना चाहते है?...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वे जानना चाहते हैं कि रिमोर्ट सेंसिग से आयरन ओर के डिपोजिट्स को आइडेंटिफाई करने के बजाय, दूसरे सोर्स से क्यों जा रहे हैं?

श्री शीश राम ओला: सर, उसका सर्वे दो-तीन तरह से होता है। एक सर्वे सैटेलाइट से भी होता है और हवाई से भी होता है। इसका पता लग जाता है कि यहां-यहां लोहा है। इससे एक नक्शा तैयार होता है। इसके बाद यह देखा जाता है कि कहां पर लोहा ज्यादा है या कहां पर मिलने की सम्भावना है। ...(व्यवधान)... और उस आयरन ओर की एक गहरी खोज होती है, तब पता चलता है कि कितना आयरन ओर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 206 ...(*Interruptions*)

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, सर, एक मिनट ...(व्यवधान)... मुझे भी एक बात पूछनी है। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अब पूरा एक ही ...(व्यवधान)... एक ही सब्जैक्ट पर नहीं हो सकता है। ...(व्यवधान)... इसमें पूछिए सप्लिमेंटरी। ...(व्यवधान)... दूसरे भी सवाल हैं। ...(व्यवधान)... आप ही सवाल पर ...(व्यवधान)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: सर, वे इसका उत्तर दे सकते हैं। ...(व्यवधान)... Sir, I have waited with patience.

श्री उपसभापति: आप बैठिए। ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं ...(व्यवधान)... देखिए, दूसरे सवाल भी हैं, दूसरे क्वैश्चन्स भी हैं। ...(व्यवधान)... एक क्वैश्चन को पंद्रह मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते। ...(व्यवधान)...